कश्मीर के मामले में पश्चिमी देशों के बयान

666. **श्री ब्रह्मदेव आनंद पासवान :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और कुछ अन्य पश्चिमी देश अपने निहित स्वार्थों के लिए कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के विषय में गलत बयानी कर 1972 के शिमला समझौते को सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं होने देना चाहते हैं;

(ख) क्या पश्चिमी देश कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का बहाना बनाकर वास्तविक मामले को गलत दिशा दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय पर अपना क्या वक्तव्य दिया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) शिमला समझौते की प्रासंगिकता को एक ऐसी रूपरेखा के तौर पर, जिसके दायरे में भारत और पाकिस्तान के बीच के अनसुलझे सभी मसलों को सुलझाया जा सकता है, अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार किया गया है जिनमें अमरीका और दूसरे पश्चिमी देश भी शामिल हैं। हालांकि उनमें प्रच्छन्न रूप से यह सोचा जा रहा है कि शिमला समझौते के आधार पर कश्मीर के मसले को सुलझाने में प्रगति नहीं हुई है लेकिन यह सोच भी विकसित हो रही है कि इसका समाधान या तो शिमला समझौते के जरिये निकलना चाहिए या ऐसे दूसरे माध्यमों से जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रोत्साहन प्राप्त हो, अमरीका का मत यह नहीं है कि शिमला समझौते पर सफलतापूर्वक अमल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह है कि इस पर अमल नहीं हुआ है और इसीलिए दूसरे तरीकों पर विचार किया जा सकता है।

(ख) जम्मू और कश्मीर के बारे में ठोस यथार्थ को और स्थिति को पूरी तरह समझे बिना वक्तव्य दिए गए हैं।

(ग) सरकार शिमला समझौते के प्रति वचनबद्ध है जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान के साथ सभी मतभेदों को शांतिपूर्वक और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए दूर किया जाना है। सरकार जम्मू और कश्मीर से सम्बद्ध घटनाओं के तथ्यों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत और आवश्यक उपाय करती रही है और आइन्दा भी करती रहेगी।

परमाणु निरस्त्रीकरण नीति के अधीन परमाणु अस्त्रों का नष्ट किया जाना

667. **श्री ब्रह्मदेव आनंद पासवान :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार कश्मीर के संदर्भ में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में भारत पर दबाव डाल रही है; और

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" में हो तो क्या भारत सरकार इस संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करना चाहेगी; यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) अमरीकी नाभिकीय अप्रसार संधि का न्यासी राज्य है और उसने इसके प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। ऐसा करने में उसने उन सभी देशों का जो अभी तक इस नाभिकीय अप्रसार संधि के सदस्य नहीं बने हैं, इस नाभिकीय अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया है।

(ख) नाभिकीय अप्रसार संधि के प्रति भारत की नीति यथावत रही है और यह कह दिया गया है कि भारत सच्चे नाभिकीय अप्रसार के उद्देश्यों के प्रति वचनबद्ध है फिर भी उसने इस नाभिकीय अप्रसार संधि पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि यह एक भेदभावपूर्ण संधि है और इसमें संसार के "नाभिकीय शक्ति प्राप्त" और "नाभिकीय शक्तिविहीन" देशों के बीच स्थायी बंटवारा करने की कोशिश है। भारत ने यह प्रस्ताव किया है कि नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार की समस्या से निपटने का एक ही तार्किक तरीका है और वह यह कि इस प्रश्न के प्रति एक ऐसा सार्वभौम तरीका अपनाया जाय जो सार्वभौमिकता, व्यापकता और भेदभाव न करने के सिद्धान्तों पर आधारित हो।

New initiative to solve the Kashmir problem

668. SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI K. K. BIRLA:
SHRI GHUFRAN AZAM:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to have a new initiative to solve the Kashmir problem;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have contemplated any serious efforts during the past few months to bring peace in the area; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (d) A number of initiatives were taken late last year for reviving normalcy and the political process in J & K. These efforts have been further intensified in the past few months. Minister of State for Internal Security has visited the State frequently and held meetings with the people at various levels. He also had interactions with local political personalities and officials at the State and district levels with a view to increasing their involvement in the normalisation process. These efforts have evoked positive responses.

Steps have also been taken to activise the local administration and to make it more responsive and accountable. District level Coordination Committees have been set up to increse the involvement of the district administration in the security operations and to strengthen the grievance redressal mechanism. Efforts have also been indicated to step up economic and developmental activities in the State, including tourism and to create employment opportunities for the youth Minister of State (Internal Security) has held a number of meetings with Central and State Government officials in this regard, both in New Delhi and Srinagar. The matter is being regularly followed up.

During a recent visit to J. & K. the Union Home Minister had clarified that the Government would like to further intensify efforts to restore the political process, by activation and involvement of all those who are willing contribute positively in this regard both at the national and the State level.

Anti-terrorism treaty with UK

669. PROF. SAURIN BHATTACHARYA:

SHRI GHUFRAN AZAM:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the treaty between India and UK regarding anti terrorism etc. has been ratified and become ecective from a very recent date;

(b) if so, whether the visiting British Secretary of State has expessed doubts over the formation of human rights body in India; and

(c) if so, what are the details thereof and further reaction of Government thereto?